(ख) यदि हां, तो उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बारोट) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने पहले ही हैदराबाद में सिक्योरटी प्रिंटिंग प्रेस स्थापित करने का फैसला कर लिया है जहां हैदराबाद टकसाल के उन कर्मचारियों को खपाने का प्रस्ताव है जिनके सिक्कों की मांग में कमी होने के कारण फालतू हो जाने की प्रत्याशा है।

प्रभावी सार्वजनिक वितरण पद्धति लागू करने के लिए योजना

1772. **श्री जैनुल बशर :**
श्री पी० के० कोडियन :
श्री ज्योतिर्मय बसु :

क्या **नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार प्रभावी सार्वजनिक वितरण पद्धति लागू करने के लिए किसी योजना पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अजमोहन महन्ती) :(क) से (ग). सार्वजनिक वितरण प्रणाली, इस देश में लम्बे अर्से से कार्य कर रही है। राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रशासनों और विभिन्न आवश्यक वस्तुओं की अधिप्राप्ति तथा आपूर्ति का कार्य करने वाले केन्द्रीय सरकार के मंत्रालय/विभागों के परामर्श से इसकी निरंतर पुनरीक्षा की जाती रहती है। आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 और चोर बाजारी तथा आवश्यक वस्तु प्रदाय बनाने रखना अधिनियम, 1980 के उपबन्धों में संसद् में पेश किए गए विधेयकों द्वारा संशोधन किया जा रहा है, ताकि इन अधिनियमों का प्रवर्तन कार्य बेहतर तरीके से किया जा सके। राज्य सरकारों इस प्रणाली को मजबूत करने के लिए आवश्यक कदम उठा रही है। जनवरी, 1980 से इस प्रणाली के बिक्री केन्द्रों में 40,000 से अधिक की वृद्धि की गई है। इस प्रणाली को मजबूत करने के एक उपाय के रुप में, देश के 12 राज्यों ने आवश्यक वस्तुओं की अधिप्राप्ति और आपूर्ति का कार्य अपने नागरिक पूर्ति निगमों को सौंप दिया है और पांच अन्य राज्य सरकारें अपने राज्यों में नागरिक पूर्ति निगमों की स्थापना करने के प्रस्तावों पर विचार कर रही हैं।

इस्पात फैक्टरियों द्वारा मांगे गए वैगन

1773. **श्री जैनुल बशर** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस्पात फैक्टरियों द्वारा 1 अप्रैल, 1981 तक मांगे गए वैगनों की संख्या क्या है;

(ख) उन्हें सप्लाई किए गए वैगनों की संख्या क्या है; और

(ग) शेष वैगनों की सप्लाई करने में विफलता के लिए रेलवे द्वारा क्या स्पष्टीकरण किया गया है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) (क) और (ख). विक्रय उत्पादों के प्रेषण के लिए अप्रल, 1980 से जनवरी, 1981 के दौरान रेलवे द्वारा इस्पात कारखानों की सप्लाई किए गए वैगनों की संख्या नीचे दी गई है:—

(4 पहिये वाले वैगनों के समतुल्य)

संयंत्र	जितने वगनों की मांग रखी गई थी	जितने वैगन दिए गए
भिलाई	1,05,350	99,352
दुर्गापुर	31,673	30,040
राउरकेला	93,836	45,964
बोकारो	90,541	85,868
इस्को (बर्नपुर)	47,033	30,020

(ग) जबकि रेलवे का कहना है कि वे इस्पात कारखानों को वगन सप्लाई करने के लिए भरसक प्रयास कर रही है तथापि वैगनों की पर्याप्त सप्लाई न होने के मुख्य-मुख्य कारण इस प्रकार हैं:—

(1) चालू वित्त-वर्ष के पहले सात महीनों में अनुपयुक्त वैगनों की संख्या निर्धारित लक्ष्य से अधिक रही है;

(2) सी०आर०टी० और बाक्स-टाइप बन्द वैगनों के अंशत: लदान पर प्रतिबन्ध;

(3) पूरे रेकों की ढुलाई पर अधिक बल देना जिससे उपलब्ध रेल के डिब्बों का इष्टतम उपयोग किया जा सके; और

(4) कुछ उपयोक्ताओं द्वारा वैगन निर्धारित अवधि से अधिक अवधि के लिए रोके रखना जिसके परिणामस्वरूप यातायात के लिए रेल डिब्बों की उपलब्धि में कमी हो जाती है । रेलवे ने बताया है कि इस्पात कारखानों में इस प्रकार का एक उपयोक्ता राउरकेला इस्पात कारखाना है ।

Export Promotion Councils

1774. SHRI K. RAMAMURTHY: Will the Minister of COMMERCE be pleased to lay a statement showing:

(a) the travelling (in foreign exchange and in rupees) and telephone expenses of the Chairman of sixteen Export Promotion Councils for the past three years;

(b) whether there are any guidelines prescribed for the Export Promotion Councils in this regard; and

(c) the contribution to the export performance of the country by these Export Promotion Councils during the past three years?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI KHURSHED ALAM KHAN): (a) The travelling and telephone expenses of the Chairman of the fifteen Export Promotion Councils during the past 3 years are given below. The sixteenth Export Promotion Council namely the Cotton Textiles Export Promotion Council, has not received any assistance from the Government for their administrative expenditure during this period.